पहली बार संभागीय आयुक्त संभालेंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगमों की कमान

राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर तीनों संभागीय आयुक्त को सौंपी जिम्मेदारी

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए 2-2 नगर निगमों को मर्ज करने के बाद अब प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। इन निगमों के बोर्ड का कार्यकाल 9 नवंबर को पूरा होगा। इसके बाद तीनों जगहों पर संभागीय आयुक्त बतौर प्रशासक इन निकायों का कामकाज संभालेंगे।

संभवत: ऐसा पहली बार हुआ है, जब शहरी सरकार की कमान प्रशासक के तौर पर सीनियर अधिकारी यानी संभागीय आयुक्तों को सौंपी है। अब तक यह काम जिला कलेक्टर या नगर निगम के कमिश्नर को दी जाती थी।

ज्ञात रहे कि प्रदेश में "सरकार वन स्टेट, वन इलेक्शन" के तहत चुनाव करवाने पर काम कर रही है। इसी के तहत प्रदेश में कई शहरी निकायों में वर्तमान में प्रशासक लगे हुए है। फरवरी 2026 तक प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। संभावना है कि सभी निकायों में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे।

स्वायत्त शासन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक इस साल दिसंबर में 50 नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा होगा। जबकि अगले साल जनवरी में 90 और फरवरी में एक निकाय का कार्यकाल पूरा होगा।

साल 2019 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में वार्डों का पुनर्गठन करते हुए दो-दो नगर निगम बनाए थे। उसके बाद प्रदेश में उस समय 196 नगरीय निकाय हो गए थे। इन्हीं सभी नगरीय निकायों में साल 2019 से 2021 तक चुनाव भी कराए गए। इसके बाद सरकार ने जनसंख्या के आधार पर कई ग्राम पंचायतों को नगरीय निकायों में क्रमोन्नत कर दिया। तब से अब तक 116 नए निकाय बनाए गए, जबकि 3 निकाय को खत्म करने की अधिसूचना कुछ माह पहले जारी की गई। इनमें जयपुर, जोधपुर और कोटा का एक-एक निकाय है। इस तरह अब कुल 309 निकाय हो गई, जिनमें इस साल के आखिरी या अगले साल चुनाव करवाए जाएंगे।

- **ज्ञात रहे कि 9 नवंबर को इन तीनों जगहों बोर्ड का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद संभागीय आयुक्त कामकाज शुरू करेंगे**
- **चर्चाएं है कि फरवरी तक प्रदेश में सभी 309 निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, इसके बाद सरकार एक साथ इन जगहों पर चुनाव करवाएगी**

महापौर-सभापति के सीधे चुनाव के अनुभव सही नहीं : मंत्री खर्रा

जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकायों (नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम) में चुनाव करवाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चाएं इस बात की है कि, निकाय प्रमुख यानी अध्यक्ष, सभापति और मेयर का चुनाव कैसे होगा। परंतु इन चर्चाओं को शुक्रवार को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने काफी हद तक विराम दे दिया। उन्होंने इस बार भी निकाय मुखिया के चुनाव अप्रत्यक्ष करवाने के संकेत दिए। मीडिया से बात करते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि, हमारे पास 2 तरह के विचार आए थे। एक समय हमने सीधे चुनाव करवाने का निर्णय करते हुए सीधे चुनाव भी करवाए थे, लेकिन उसमें बड़ी दिक्कत सामने आई थी। मुखिया किसी और अन्य विचारधारा का निर्वाचित हो गया। बोर्ड किसी अन्य विचारधारा वाला निर्वाचित हो गया। इस कारण उनमें पूरे पांच साल खींचतान चलती रही। अगर इस खींचतान का कोई समाधान निकलेगा तो हम उस पर विचार करेंगे अन्यथा वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है उसी पर काम करेंगे। ज्ञात रहे कि वर्ष 2009 डायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए थे। तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। नगरीय निकायों में मुखिया के चुनाव प्रत्यक्ष (सीधे जनता द्वारा चुनने की प्रक्रिया) तौर पर करवाए थे। इस दौरान जयपुर नगर निगम में बोर्ड तो भाजपा का निर्वाचित होकर आया, लेकिन मेयर उस समय कांग्रेस की जीती थी। तब बोर्ड और मेयर में जबरदस्त विवाद रहा था। इस कारण तब लम्बे समय तक नगर निगम में संचालन समितियां नहीं बन सकी थी।

- **मंत्री खर्रा ने निकाय प्रमुख के अप्रत्यक्ष चुनाव के संकेत कहा कि "पूर्व में जब सीधे चुनाव हुए तो मुखिया और बोर्ड अलग-अलग विचारधारा वाले आए, जिससे 5 साल खींचतान रही"**

निम्बाहेडा-मगंलवाड फोर लेन सड़क के लिए 260 करोड के ऋण को मंजूरी दी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट कोर्पोरेशन की 129वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की।

जयपुर (कासं)। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट कोर्पोरेशन की 129वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए निम्बाहेडा-मगंलवाड सडक फोरलेनकरण कार्य के लिए नाबार्ड से लिए जा रहे 260 करोड रुपए के लोन को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ उन्होंने उन्होंने कम ब्याज दरों के कारण हुडको से नाबार्ड को शिफ्ट किए जा रहे 175 करोड़ रुपये के लोन की शिफ्टिंग को भी मंजूरी दी।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आरएसआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में आरएसआरडीसी के टर्न ओवर एवं लाभ में वृद्वि की सराहना करते हुए अधिकारियों से कहा की,कोस्ट सेन्ट्रिक अप्रोच के साथ काम कर प्रोजेक्ट वाइज कोस्टशीट तैयार करके उसका परीक्षण करे ताकि हर प्रोजेक्ट की वास्तविक लागत ,लाभ-हानि की सही जानकारी मिल सके।

आरएसआरडीसी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुये उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश के रोड कॉर्पोरेशन के मॉडल की स्टडी करें ताकि आरएसआरडीसी को वित्तीय रूप से मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के कॉर्पोरेशन जो बेहतरीन काम कर रहे है उनकी बेस्ट प्रेक्टिसेज को प्रदेश में लागू किया जाये। उपमुख्यमंत्री ने आरएसआरडीसी के कार्यो में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की बात कहते हुये क्वालिटी कन्ट्रोल विंग को सुदृढ करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि जो भी परियोजनाऐं संचालित की जा रही है वे निश्चित समय अवधि में पूरी होनी चाहिए। इस दौरान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव आयोजना भवानी सिंह देथा, शासन सचिव वित्त नवीन जैन, शासन सचिव पीडब्ल्यूडी डीआर मेघवाल सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं आरएसआरडीसी के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

डीजीपी ने दी पुलिसकर्मियों को दीपावली की बधाई

पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को मिठाईयां भेंट करते हुए दीपावली की बधाई दी।

जयपुर । पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं तथा उन्हें नई ऊर्जा, समर्पण और विश्वास के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने का आव्हान किया।

इस अवसर पर डीजीपी शर्मा ने कहा कि दीपावली केवल प्रकाश का पर्व नहीं बल्कि सकारात्मकता, विश्वास और सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, यदि हमारे भीतर विश्वास और संकल्प की ज्योति जलती रहे तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। शर्मा ने कहा कि यह दीपावली पुलिस संगठन के लिए एक नए युग की शुरुआत है, क्योंकि देश में लागू हुए नवीन आपराधिक कानूनों के साथ न्याय प्रणाली में नई सोच और नई दिशा आई है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि न्याय को अधिक मानवीय, त्वरित और नागरिक-केंद्रित बनाना है। डीजीपी ने हाल ही में आयोजित नव विधान-न्याय की पहचान प्रदर्शनी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं था बल्कि पुलिस विभाग की तैयारी, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास का परिचायक था। इस प्रदर्शनी ने यह सिद्ध किया कि जब परंपरा और तकनीक साथ चलते हैं तो पुलिसिंग और भी आधुनिक और प्रभावी बनती है।

परिणय जैन पहुंचे इंडियन आइडल सीजन 16 के टॉप 30 में

जयपुर (कासं)। देश के लोकप्रिय रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल सीजन 16' में पिंक सिटी के युवा गायक परिणय जैन बाकलीवाल ने अपनी मधुर आवाज और उम्दा प्रस्तुति के साथ टॉप 30 में अपनी जगह बनाकर एक बार फिर जयपुर का मान बढ़ाया है। हाल ही में प्रसारित एपिसोड में उनकी ऊर्जावान परफॉरमेंस ने जजों को मंत्रमुग्ध कर दिया और प्रसिद्ध गायिका व शो की जज श्रेया घोषाल ने उनकी गायकी की सराहना करते हुए कहा कि उनकी आवाज़ में गहराई और भावनाओं का अद्भुत संतुलन है।" गायन के साथ-साथ परिणय गिटार, की-बोर्ड, ड्रम्स और ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों में भी पारंगत हैं। परिणय के दादा राजा बाबू बाकलीवाल बस्सी वाले ने बताया कि संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपनी मां श्वेता बाकलीवाल और उसके उपरांत डॉ. विजेन्द्र गौतम से शास्त्रीय संगीत सीखा है। जिनेश कुमार जैन ने बताया परिणय रेडियो सिटी जूनियर सुपर सिंगर, जयपुर आइडल और सुर संगम जैसी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीत चुके हैं।

पहली बार किसी सरकारी सेवा पर उपभोक्ता दे सकेंगे "स्टार रैटिंग"

विद्युत सेवाओं में सुधार के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम की पहल

डिस्कॉम्स चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने शुक्रवार को सभी जोनल मुख्य अभियंताओं तथा अधीक्षण अभियंताओं के साथ बैठक की।

जयपुर । जयपुर विद्युत वितरण निगम ने अपनी विद्युत सेवाओं में सुधार कर इसे कंज्यूमर फ्रेंडली, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में अनूठी पहल की है। इस प्रक्रिया में जयपुर डिस्कॉम नया घरेलू कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से फीडबैक लेने जा रहा है। प्रदेश में आमजन से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाले किसी राजकीय निगम अथवा विभाग ने पहली बार निजी सेवा प्रदाता कंपनियों की तरह उपभोक्ताओं से फीडबैक लेने की ऐसी शुरूआत की है। फिलहाल नए घरेलू कनेक्शन को इसके दायरे में लिया गया है। धीरे-धीरे निगम की अन्य सेवाओं को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने शुक्रवार को सभी जोनल मुख्य अभियंताओं तथा अधीक्षण अभियंताओं के साथ फीडबैक मैकेनिज्म की तैयारियों की समीक्षा की और सोमवार से इसे प्रारंभ करने के निर्देश दिए। अब जो भी नए घरेलू कनेक्शन जारी होंगे उनमें फीडबैक देने की यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। निगम का प्रयास है कि 1 अक्टूबर से जो घरेलू कनेक्शन दिए गए हैं, उनमें भी ऐसा फीडबैक लिया जाए। नया घरेलू कनेक्शन जारी होने के बाद आवेदक को मोबाइल एप्लीकेशन 'बिजली मित्र 'डाउनलोड करने का एसएमएस प्राप्त होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही 'के' नम्बर डालने पर उपभोक्ता को फीडबैक पॉप अप दिखाई देने लगेगा। इस पॉप अप पर क्लिक करते ही उपभोक्ता कनेक्शन प्राप्त करने के अपने अनुभव 1 से 5 स्टार रेटिंग के जरिए प्रदान कर सकेंगे। इस दौरान वे अन्य वैकल्पिक टिप्पणियां भी जोड़ सकेंगे। एक से 2 स्टार रेटिंग के मामलों में अधिकारी नियमित समीक्षा करेंगे और सेवा में सुधार के उपाय सुनिश्चित करेंगे। डिस्कॉम द्वारा इनकी नियमित मॉनीटरिंग की जाएगी। वृत्त तथा सब डिविजन स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षा होगी। इसके आधार पर अधीक्षण अभियंता तथा सहायक अभियंता कार्यालयों की भी रैंकिंग तय होगी।

इस प्रक्रिया से निचले स्तर तक मॉनीटरिंग आसान होगी। कनेक्शन जारी करने में कई बार देरी की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे में स्वतंत्र फीडबैक लेने से वास्तविक स्थिति सामने आ पाएगी। इससे सेवाओं को त्वरित, बेहतर, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने में डिस्कॉम प्रबंधन को मदद मिलेगी। उन अधिकारियों अथवा कार्मिकों की भी मॉनीटरिंग हो सकेगी जो आम आदमी से जुड़ी सेवाओं की अदायगी में लापरवाही बरतते हैं अथवा उन्हें लटकाते हैं।

उल्लेखनीय है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम ने कुछ दिन पूर्व ही बिजली कनेक्शन को लेकर उपभोक्ताओं से फीडबैक लेने में हैल्पलाइन सेवा 181 का भी सहयोग लिया था। इस प्रक्रिया में 1 अप्रैल, 2025 से 15 अगस्त 2025 के दौरान विद्युत कनेक्शन लेने वाले 75 हजार 746 उपभोक्ताओं को मोबाइल पर कॉल किए गए। जिन 41 हजार 815 उपभोक्ताओं ने कॉल रिसीव किए।

सार-समाचार

ऑर्गेनिक फूड मार्केट का शुभारंभ

जयपुर, (कासं)। राज्य में जैविक खेती से जुड़े उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तथा उपभोक्ताओं को प्रमाणित जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाने की दृष्टि से कृषि एवं कृषि विपणन विभाग द्वारा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना की गई है। ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना का मुख्य ध्येय जैविक उत्पादकों को अपने उत्पाद का प्रचार-प्रसार करने हेतु प्लेट फार्म उपलब्ध कराना एवं उपभोक्ताओं को प्रमाणित जैविक उत्पाद उपलब्ध कराना हैं। ऑर्गेनिक मार्केट का संचालन राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक शनिवार व रविवार को प्रात: 10 बजे से सांय 6 बजे तक किया जा रहा है। राजस्थान बीज एवं जैविक प्रमाणिकरण संस्था द्वारा जारी स्कॉप-सर्टिफिकेट धारी जैविक उत्पादक इस मार्केट में अपने उत्पाद विक्रय हेतु ला सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड मार्केट में जैविक उत्पादों के लिए 10 स्थान उपलब्ध हैं। इस मार्केट में उत्पादकों को नि:शुल्क स्थान उपलब्ध करवाया गया है इच्छुक प्रमाणित जैविक उत्पादक निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा को ऑर्गेनिक मार्केट में स्थान आवंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

कर्मचारी संघ का अधिवेशन 26-27 को

जयपुर। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ का 11वां प्रान्तीय अधिवेशन 26 व 27 अक्टूबर को सामुदायिक केन्द्र सेक्टर 8 अरावली मार्ग मानसरोवर जयपुर में आयोजित होगा। संयुक्त महासचिव एवं प्रचार प्रसार समिति संयोजक गोविन्द नाटाणी ने बताया कि अधिवेशन के प्रथम दिवस 26 अक्टूबर को प्रात: 9.15 बजे झण्डारोहण के साथ प्रदेश अध्यक्ष दशरथ कुमार के अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारम्भ किया जायेगा। अधिवेशन के प्रथम अधिवेशन में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं आवासन मण्डल अध्यक्ष डॉ. देबाशीष पृष्टी, आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, सचिव गोपाल सिंह, वित्तीय सलाहकार रोहिताश्व यादव, अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों सहित आवासन मण्डल के पूर्व अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। प्रथम दिवस के प्रथम चरण में कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री प्रदीप शर्मा द्वारा कर्मचारी संघ के किये गये कार्यो की रिपोर्ट का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। दूसरे चरण में प्रदेशभर से आये शाखा अध्यक्षों सहित मण्डल के कर्मचारियों के द्वारा खुला मंच में मण्डल एवं कर्मचारियों के बारे में विस्तृत चर्चा करने के साथ ही महामंत्री के प्रतिवेदन पर चर्चा की जायेगी। अधिवेशन के द्वितीय दिवस में प्रान्तीय अध्यक्ष के चुनाव अधिकारी टी.एस. मीणा को नियुक्त एवं सहायक चुनाव अधिकारी आर.पी. शर्मा एवं जगमोहन सिंह राठौड को नियुक्त किया गया।

बंदूक की नोंक पर नगदी-जेवरात लूटे

जयपुर। मुहाना थाना इलाके में शुक्रवार को एक घर में अकेली महिला से लूट की वारदात होने का मामला सामने आया है। लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को लूट की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस और एसीपी मानसरोवर मौके पर पहुंच कर घटनाक्रम की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पडताल में जुटी है। पुलिस के अनुसार पीड़ित शंकर सिंह ने मामला दर्ज करवाया है कि वह मुहाना मंडी में व्यापार करता है और रोज की तरह वह व्यापार के लिए घर से निकला था। शुक्रवार सुबह जब करीब 10 बजे घर पहुंचा तो पत्नी रो रही थी। पत्नी ने बताया कि दो लड़के और एक लड़की जबरन घर में घुस आए और बंदूक दिखाकर उसे डरा कर घर में रखी नकदी और जेवरात लूटे और मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने एक-एक करके समय लेकर घर से निकले। ताकि किसी को उन पर शक न हो। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम को बुलाया है। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। पुलिस की कुछ टीमें संदिग्धों से इस संबंध में पूछताछ कर रही हैं।

कैडर पुनर्गठन के निर्देश जारी हुए

जयपुर। वित्त (ग्रुप 3) विभाग ने वर्ष 2025-26 में की गई बजट घोषणा के अनुरूप मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के विभागों में कैडर पुनर्गठन के निर्देश जारी किए हैं । निर्देशानुसार सभी संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव आदि अधिकारियों को उनके अधीनस्थ विभागों में वित्त विभाग की अर्द्ध शासकीय टिप्पणी 16 अक्टूबर में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नित के पद पुनर्गठन के आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कर्मचारी महासंघ एकीकृत द्वारा बजट घोषणाएं वर्ष 2025-26 की क्रियान्वित के लिए निरंतर आंदोलन किया जा रहा है तथा कार्मिक शासन सचिव शुचि त्यागी द्वारा दीपावली से पूर्व प्राथमिक वार्ता भी की गई थी । इसी क्रम में आज यह निर्देश जारी किए गए हैं। अब मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नित के पदों का प्रतिशत संस्थापन अधिकारी 1.6 प्रतिशत, प्रशासनिक अधिकारी 4.5 प्रतिशत, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 10 प्रतिशत एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 17 प्रतिशत पद निर्धारित किए गए हैं जबकि यदि किसी विभाग में कुल संख्या 35 से या उससे अधिक हुई तो उसमें भी कम से कम एक संस्थापन पदाधिकारी तथा 20 या उससे अधिक होने पर एक प्रशासनिक अधिकारी का पद क्रमोन्नत किया जाएगा। पुनर्गठन में प्रतिशत 0.5 प्रतिशत की आवश्यक अधिक होने पर एक पद माना जाएगा। सरकार को संविदा कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग के अधीन एक संस्था गठित करने के लिए विभागों से सूचना मांगे जाने का भी स्वागत किया है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री एवं महासंघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरूका ने महासंघ के मंत्रालयिक कर्मचारियों को दूसरी पदोन्नित पर 4200 ग्रेड पे दिए जाने सहित 22 सूत्री मांग पत्र पर भी शीघ्र वार्ता कर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

हर जिले में एक ब्लॉक विकसित बनाने के लिए सरकार ने शुरू की 'गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अभिनव पहल से "विकसित राजस्थान" का संकल्प हो रहा साकार

जयपुर (कासं)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश में आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक्स का समावेशी एवं सतत विकास सुनिश्चित हो रहा है। प्रधानमंत्री की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रदेश के सभी 41 जिलों के एक-एक ब्लॉक में गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना भी शुरू की है।

अविकसित जिलों के उत्थान के लिए जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) 112 जिलों में शुरू किया गया। इसके अन्तर्गत राजस्थान के पांच जिलों बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके तहत अब तक बारां को 17.51 करोड़ रुपये, धौलपुर को 15.82 करोड़ जैसलमेर को 9.62 करोड, करौली को 9.05 करोड़ औऱ सिरोही को 4.81 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्राप्त हो चुकी है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम से जिलों में आए सकारात्मक बदलाव, सफलता और विकास को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने के लिए जनवरी 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 27 ब्लॉक किशनगंज, बसेड़ी, फतेहगढ़, मासलपुर, आबूरोड, नीमराना, सज्जनगढ, रामसर, वैर, कोटड़ी, कोलायत, केशवरायपाटन, निम्बाहेडा, राजगढ़, रामगढ पचवारा, झोंथरी, संगरिया, अहोर, खानपुर, शेरगढ, जायल, रानी, पीपलखूंट, भीम, गंगापुर सिटी, पीपलू और खेरवाडा शामिल हैं। इन ब्लॉक में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, बुनियादी ढांचा और कौशल विकास के क्षेत्र में काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के जरिए सभी चिन्हित ब्लॉकों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, आधारभूत संरचना, कौशल विकास एवं सामाजिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार आधारित कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए 39 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को आधार बनाया गया है। इस योजना की विभिन्न स्तर पर निगरानी की जाएगी। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियां कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करेंगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति और जिला क्लक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय समितियां बनाई गई हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में आकांक्षी ब्लॉक्स के विकास के लिए 75 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रत्येक ब्लॉक के लिए 1.5 करोड़ रुपये (अनटाइड निधि) का प्रावधान शामिल है। योजना से संबंधित 30 ब्लॉकों से प्लान ऑफ एक्शन प्राप्त हो चुके हैं। योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को प्रोत्साहन स्वरूप वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पहला स्थान प्राप्त करने ब्लॉक को 50 लाख रुपये, दूसरे स्थान को 35 लाख, तीसरे स्थान को 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना में भिनाय, रामगढ़, सिणधरी, गढ़ी, शाहबाद, चौहटन, मसूदा, भूसावर, करेडा, बीकानेर, तालेडा, गंगरार, चूरू, सिकंदरा, पहाड़ी, सैपऊ, नावा, गलियाकोट, भादरा, चाकसू, सम, जालौर, झालरापाटन, झुंझूनूं, सेखाला, करौली, तिजारा, लाडपुरा, बानसूर, मेडता, बाली, आऊ, धमोतर, कुंभलगढ़, खंडार, सराड़ा, खंडेला, पिंडवाड़ा, सादुलशहर, उनियारा, कोटड़ा ब्लॉक शामिल हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए अब तक सभी चयनित ब्लॉकों द्वारा बेसलाइन डाटा संग्रहण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं सभी चयनित ब्लॉकों से ब्लॉक विकास रणनीति प्राप्त हो चुकी है।

उदयपुर जिले का जनजाति बहुल खेरवाड़ा ब्लॉक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं और जनजागरूकता की कमी के कारण 2 साल पहले तक कुपोषण और कम प्रसव पूर्व देखभाल (एएनसी) पंजीकरण सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था। आकांक्षी ब्लॉक विकास कार्यक्रम में जुडने के बाद संपूर्णता अभियान, एएनसी खोजो अभियान, स्वस्थ धरोहर शिविरों जैसी गतिविधियों और कंगारू मदर केयर जैसे अभिनव नवाचारों ने खेरवाडा ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी है।

एएनसी खोजो अभियान चलाकर प्रत्येक गर्भवती महिला की पहचान व 12 सप्ताह के भीतर उनका पंजीकरण सुनिश्चित किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2023 में जहां एएनसी पंजीकरण दर 60 प्रतिशत थी, वहीं 2025 तक यह 90 प्रतिशत तक पहुंच गई। पंचायत स्तर पर महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित किया गया जिससे संस्थानिक प्रसवों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। साथ ही, कुपोषण और एनीमिया के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई।

स्वस्थ धरोहर शिविरों के माध्यम से उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अन्य असंचारी रोगों की जांच की गई। खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज स्थापित किया गया, जहां कम वजन वाले शिशुओं (1800-2500 ग्राम) को उनकी माताओं के साथ त्वचा से त्वचा सम्पर्क में रखा जाता है। इससे शिशु का तापमान नियंत्रित रहता है और उसका वजन भी तेजी से बढ़ता है।

उदयपुर के जनजाति बहुल खेरवाड़ा ब्लॉक में तैयार कंगारू मदर केयर वार्ड।

- **प्रदेश के 5 जिले और 27 ब्लॉक में समावेशी और समग्र विकास हो रहा सुनिश्चित**